

Daily Current Affairs

Date : 21 May, 2026

UTKARSH
CLASSES

CIVIL
SERVICES

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	राजस्थान में 'ग्राम विकास चौपाल'
2.	राज्य गोडावण दिवस (21 मई)
3.	आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) में राजस्थान
4.	'एक जिला एक उत्पाद नीति' (ODOP) में परिवर्तन
5.	राजस्थान में 'माय भारत पोर्टल' की प्रगति
6.	राजस्थान के 2 शिक्षा नवाचारों को मिला 'गुड स्टेट प्रैक्टिसेज' का दर्जा
7.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. जनगणना के अंतर्गत 'स्वगणना अभियान' में जयपुर प्रदेश में प्रथम
8.	प्रधानमंत्री की बहु-राष्ट्रीय यात्रा
9.	"अरुणाचल कीवी: अरुणाचल प्रदेश की USP" मिशन
10.	न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968
11.	व्यापार सक्षमीकरण और बाजार-पहुंच (TEAM - टीम) पहल
12.	वीनस ऑर्बिटर मिशन (VOM)
13.	हॉप प्रयोग
14.	बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति (PRAGATI), 2026
15.	अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्चड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल (ULPGM-V3)

--:1:--



राजस्थान परिदृश्य



राजस्थान में 'ग्राम विकास चौपाल'



चर्चा में क्यों?

- 21 मई, 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डूंगरपुर के धम्बोला गाँव में 'ग्राम विकास चौपाल' में भाग लिया।

DIPR
RAJASTHAN

ग्राम विकास चौपाल

महिलाओं, किसानों, युवाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों से आत्मीय संवाद

राजीविका से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक संबल मिल रहा है। महिलाओं के बैंक सखी, कृषि सखी और पशु सखी बनने से सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं।

-श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान

f i X v /DIPRRajasthan

--2--



मुख्य बिन्दु:

- इससे पूर्व 20 मई, 2026 को बाँसवाड़ा के कुशलगढ़ स्थित चुड़ादा गाँव में भी मुख्यमंत्री ने 'ग्राम विकास चौपाल' कार्यक्रम में भाग लिया था। मुख्यमंत्री द्वारा बाँसवाड़ा में राजीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए CLF कार्यशाला बनवाने एवं उत्पादों की पैकेजिंग यूनिट स्थापित करने सम्बन्धी निर्देश जारी किये गए।
- इस अवसर पर स्थानीय कलाकारों ने मुख्यमंत्री को आदिवासी अंचल की पारंपरिक 'आदिवासी बंडी' (जैकेट) एवं तीर-कमान भेंट किया।
- राजस्थान में 'ग्राम विकास चौपाल' के तहत मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के विभिन्न गाँवों का दौरा कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया जा रहा है।
- इस जन-संपर्क अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य और केन्द्र सरकार की लोक-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना और ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना है।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री द्वारा अब तक 'ग्राम विकास चौपाल' कार्यक्रम के अंतर्गत 7 जिलों में भ्रमण किया जा चुका है।

क्रम	गाँव
1.	बम्बोरी गाँव (प्रतापगढ़)
2.	जाजोद गाँव (सीकर)
3.	कड़ैल गाँव (अजमेर)
4.	पंसेरी गाँव (जालौर)
5.	ठीकरिया गाँव (जयपुर)
6.	चुड़ादा गाँव (बाँसवाड़ा)
7.	धम्बोला गाँव (डूंगरपुर)

- **ठीकरिया गाँव (जयपुर) :** मुख्यमंत्री द्वारा इसी स्थान से राज्य स्तरीय ग्राम विकास चौपाल और रथ यात्रा कार्यक्रम के समापन समारोह को सम्बोधित किया गया।

राज्य गोडावण दिवस (21 मई)

चर्चा में क्यों?

- राजस्थान में प्रति वर्ष 21 मई को राज्य गोडावण दिवस (Great Indian Bustard Day) के रूप में मनाया जाता है।

मुख्य बिन्दु:

- ज्ञातव्य है कि 21 मई, 1981 को ही गोडावण (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) को राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण) :

- वैज्ञानिक नाम :** अर्डोटिस निग्रिसेप्स (Ardeotis Nigriceps)

- अन्य नाम :** सोन चिड़िया।

- सर्वाधिक संख्या :** मरू राष्ट्रीय उद्यान (जैसलमेर), सांखलिया (अजमेर) तथा सोरसेन (बारां)

- गोडावण प्रजनन केंद्र :** सुदासरी (जैसलमेर), सोरसेन (बारां) तथा जोधपुर।

- गोडावण हैचिंग सेंटर (कृत्रिम प्रजनन केंद्र) :** रामदेवरा (जैसलमेर)

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :

- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) भारत में पाई जाने वाली चार बस्टर्ड प्रजातियों में से सबसे बड़ी हैं, अन्य तीन-मैकक्वीन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन और बंगाल फ्लोरिकन।



Daily Current Affairs

Date : 21 May, 2026



- GIB का प्राकृतिक आवास मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप था, लेकिन समय के साथ यह घटकर केवल राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान तक सीमित रह गया है।
- GIB को उपोष्ण कटिबन्धीय घास के मैदानों की प्रमुख पक्षी प्रजाति माना जाता है।
- भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) की आबादी गिरकर 300 से भी कम रह गई है।

संरक्षण प्रयास:

- भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 : अनुसूची I में।
- **CITES** : परिशिष्ट I में।
- **प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन (CMS)** : परिशिष्ट I में।
- **IUCN की रेड लिस्ट** : गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered)
- 5 जून, 2013 को राजस्थान सरकार द्वारा 'प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' नामक महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
- कार्यक्रम के तहत, भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) और राजस्थान वन विभाग ने संयुक्त रूप से संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किए हैं।

--:5:--

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) में राजस्थान

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राजस्थान में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के अंतर्गत सभी 41 जिलों में एक राजकीय एवं एक निजी स्वास्थ्य संस्थान का चयन किया गया है, जिन्हें 'मॉडल फैसिलिटी' के रूप में विकसित किया जाएगा।



मुख्य बिन्दु:

- मॉडल फैसिलिटी के रूप में चयनित इन संस्थानों को स्पेशल सपोर्ट देकर डिजिटल किया जाएगा और इनमें एंड-टू-एंड ABDM के सभी कॉम्पोनेन्ट; जैसे - स्कैन एंड शेयर, ABDM कम्प्लायंट हेल्थ मैनेजमेंट इंफोर्मेशन सिस्टम एडॉप्शन, हेल्थकेयर फैसिलिटी रजिस्ट्री और हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री करवाकर, सभी मरीजों की ABHA ID बनाकर हेल्थ रिकॉर्ड लिंक किया जाएगा।

--6--

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स :

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 27 सितंबर, 2021 को लॉन्च किए गए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सक्रिय सहयोग के माध्यम से एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM), जिसे पूर्व में 'राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन' के रूप में जाना जाता था, का उद्देश्य कुशल, सुलभ, समावेशी, किफायती, समयबद्ध और सुरक्षित तरीके से सार्वभौमिक (Universal) स्वास्थ्य कवरेज का समर्थन करना है।

आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA)

- ABHA 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' का भाग है।
- **सम्बन्धित मंत्रालय** : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।
- **उद्देश्य** : नागरिकों के स्वास्थ्य अभिलेखों का केंद्रीकृत, सुरक्षित एवं डिजिटल संग्रह सुनिश्चित करना।
- राजस्थान में दिसंबर, 2025 तक 6.52 करोड़ से अधिक ABHA ID बनाई जा चुकी है।
- **नोट** : राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाने के लिये 'स्वास्थ्य सेवा का अधिकार अधिनियम, 2023' क्रियान्वित किया जा रहा है।

'एक जिला एक उत्पाद नीति' (ODOP) में परिवर्तन



चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए संचालित की जा रही 'एक जिला एक उत्पाद नीति (ODOP) - 2024 में दो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं।



#OneDistrictOneProduct

RAJASTHAN'S

One District One Product (ODOP) Policy

Empowering Entrepreneurs

Rajasthan is unlocking limitless possibilities for entrepreneurs through its ODOP (One District One Product) Policy, offering substantial margin money assistance to fuel new micro and small enterprises.



Margin Money Assistance for New Enterprises

1. Micro Enterprises: 25% subsidy (up to INR 15 lakh)
2. Small Enterprises: 15% subsidy (up to INR 20 lakh)



Additional subsidy of up to INR 5 lakh for

1. Women Entrepreneurs
2. Young Entrepreneurs (below 35 years)
3. People with Benchmark Disabilities (PwBD)
4. SC/ST Entrepreneurs

RISING.RAJASTHAN.GOV.IN

X in @ f

#RISINGRAJASTHAN

--8:--



मुख्य बिन्दु:

- उल्लेखनीय है कि राज्य बजट 2026-27 में ODOP इकाइयों को विस्तार के लिए मार्जिन मनी देने की घोषणा की गई थी।
- **प्रथम संशोधन** : उद्यमों का विस्तार करने वाली सूक्ष्म इकाइयों को 20 लाख रुपये और लघु श्रेणी इकाइयों को 15 लाख रुपये तक का मार्जिन मनी अनुदान मिल सकेगा। इसके लिए 15 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है। पूर्व में केवल नई इकाइयों को ही यह लाभ प्राप्त होता था।
- **द्वितीय संशोधन** : ODOP नीति के तहत अब निजी संस्थानों के माध्यम से भी तकनीकी अपग्रेडेशन कर सकेंगे तथा इसके लिए 5 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। पूर्व में यह लाभ केवल राजकीय संस्थानों के माध्यम से तकनीक अपग्रेडेशन करने पर ही दिया जाता था।
- इस बदलाव से ODOP इकाइयाँ नवीनतम तकनीक और मशीनें आसानी से ले सकेंगी, जिससे कम ऊर्जा खपत के साथ गुणवत्तापूर्ण उत्पादन हो सकेगा।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु :

- हाल ही में, राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली पंच गौरव कार्यक्रम की राज्य स्तरीय समिति ने पाँच जिलों में कुल ₹18.19 करोड़ की लागत से स्थापित होने वाली 5 नवीन परियोजनाओं को स्वीकृति दी।
- चयनित 5 ज़िलों; दौसा, चूरू, डीडवाना-कुचामन, फलौदी और बालोतरा में कॉमन फैसिलिटी सेंटर, टेस्टिंग लैब और भंडारण के लिए सुविधाएँ विकसित की जाएंगी।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स :

एक जिला एक उत्पाद नीति-2024:

- राज्य के विशिष्ट उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी 41 जिलों में एक-एक उत्पाद की पहचान कर 'एक जिला एक उत्पाद नीति-2024' की शुरुआत की गई है।

Daily Current Affairs

Date : 21 May, 2026



- संबंधित विभाग : उद्योग एवं वाणिज्य विभाग (राजस्थान सरकार)
- नीति का शुभारंभ : दिसंबर, 2024
- वैधता : 31 मार्च, 2029 तक वैध।
- इसके तहत राज्य सरकार द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

प्रोत्साहन :

क्र. सं.	प्रोत्साहन	वित्तीय सहायता
1.	मार्जिन मनी सहायता	₹20 लाख तक।
2.	एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर	₹5 लाख तक।
3.	क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर	₹3 लाख तक।
4.	विपणन आयोजनों में भाग लेने के लिए	₹2 लाख तक।
5.	ई-कॉमर्स वेबसाइट विकास के लिए	₹75 हजार तक

--:10:--

राजस्थान में 'माय भारत पोर्टल' की प्रगति

चर्चा में क्यों?

- 20 मई, 2026 तक राजस्थान में लगभग 17.70 लाख युवा 'माय भारत पोर्टल' पर पंजीकृत हो चुके हैं। पोर्टल पर 49 विश्वविद्यालय, 420 कॉलेज एवं 243 विद्यालय ऑनबोर्ड किए जा चुके हैं।

माय भारत पोर्टल की प्रगति की समीक्षा बैठक

- 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का व्यापक पंजीकरण सुनिश्चित करने पर जोर
- माय भारत पोर्टल युवाओं के लिए, 'सिंगल विंडो सॉल्यूशन' के रूप में विकसित हो

- मुख्य सचिव

मुख्य बिन्दु:

- साथ ही, 13 विभागों एवं 9 जिला प्रशासन को भी इस पोर्टल से जोड़ा गया है तथा 942 अनुभवात्मक शिक्षण अवसर एवं 10,000 स्वयंसेवी मौके पब्लिश किये गए।
- माय भारत (मेरा युवा भारत) पोर्टल भारत सरकार की एक पहल है, जो युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत देश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है।
- लॉन्च** : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर, 2023 को।
- यह एक सेंट्रल हब के रूप में कार्य करता है, जो 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं को अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रमों, स्वयंसेवा के अवसरों और मेंटरशिप नेटवर्क से जोड़ता है।

राजस्थान के 2 शिक्षा नवाचारों को मिला 'गुड स्टेट प्रैक्टिसेज' का दर्जा

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, नीति आयोग ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट 'स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया-टेम्पोरल एनालिसिस एण्ड पॉलिसी रौडमैप फॉर क्वालिटी इन्हेंसमेंट' में राजस्थान के 'शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान' एवं मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के AI आधारित मूल्यांकन प्रणाली को 'गुड स्टेट प्रैक्टिसेज' के रूप में उल्लेखित किया गया है।

नीति आयोग की स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया पर नवीनतम रिपोर्ट

- राजस्थान के शिक्षा नवाचारों पर नीति आयोग ने लगाई मुहर
- 'शाला स्वास्थ्य अभियान एवं एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली को बताया गुड स्टेट प्रैक्टिसेज'

**मुख्यमंत्री के नेतृत्व में,
राजस्थान का शिक्षा क्षेत्र बन रहा
नवाचारों की उत्कृष्ट पाठशाला**

RajGovOfficial

--:12:--

मुख्य बिन्दु:

- नीति आयोग ने रिपोर्ट में राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण, फिटनेस एवं स्वास्थ्य निगरानी के लिए विकसित 'शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान' की सराहना की है।
- रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 75 लाख से अधिक विद्यार्थियों की 70 से अधिक स्वास्थ्य मानकों पर स्क्रीनिंग की गई है। इसके तहत विद्यार्थियों की दृष्टि, श्रवण क्षमता, पोषण स्तर, दंत स्वास्थ्य व शारीरिक फिटनेस सहित विभिन्न पहलुओं की जाँच एवं मोबाइल ऐप आधारित फॉलो-अप प्रणाली विकसित की गई।
- नीति आयोग ने इस नवाचार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप शिक्षा प्रणाली में स्वास्थ्य एवं पोषण को अहम हिस्सा बनाने की दिशा में प्रभावी कदम बताया है।
- साथ ही, नीति आयोग ने रिपोर्ट में 'मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान' के OCR तकनीक व AI आधारित मूल्यांकन प्रणाली की भी सराहना की है।
- रिपोर्ट के अनुसार, इस मूल्यांकन प्रणाली के जरिए 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों को "लर्निंग पॉवर्टी" से बाहर निकालने में मदद मिली तथा अधिगम स्तर में 8-10 प्रतिशत वार्षिक सुधार दर्ज हुआ।
- वहीं, राजस्थान परख रिपोर्ट, 2024 में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन करते हुए देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल रहा।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु:

- **पढ़ाई विद AI कार्यक्रम** : नीति आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में टोंक जिले में संचालित 'पढ़ाई विद AI कार्यक्रम' का भी उल्लेख किया गया है, जिसके माध्यम से गणित सहित विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों के परिणाम में प्रभावी सुधार बताया गया है।

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>जनगणना के अंतर्गत 'स्वगणना अभियान' में जयपुर प्रदेश में प्रथम</p> <ul style="list-style-type: none">■ जनगणना संचालन, 2026 के अंतर्गत संचालित स्वगणना अभियान में जयपुर जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया।■ जयपुर द्वारा 3.25 लाख से अधिक स्वगणना दर्ज की गई, जो राज्य की कुल स्वगणना उपलब्धि का लगभग 22 प्रतिशत है।■ इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास द्वारा जिला कलेक्टर संदेश नायक एवं नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा को सम्मानित किया गया।



राष्ट्रीय परिदृश्य

प्रधानमंत्री की बहु-राष्ट्रीय यात्रा

{स्रोत: PIB, AIR, DD- NEWS, विदेश मंत्रालय}

चर्चा में क्यों?

- भारतीय प्रधानमंत्री ने 15 से 20 मई, 2026 के मध्य क्रमशः संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा सम्पन्न की।

वैश्विक संकट के बीच भारत के लिए बड़ी उपलब्धियां



UAE के साथ		30 मिलियन बैरल रणनीतिक तेल भंडारण साझेदारी
		भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर में \$5 बिलियन का नया निवेश
		दीर्घकालिक LNG और ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी
नीदरलैंड्स के साथ		ASML-Tata सेमीकंडक्टर समझौता
		गुजरात में पहला 300mm सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट
		\$11 बिलियन का फंड निवेश
स्वीडन के साथ		रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती
		6G और टेलीकॉम सहयोग का विस्तार
		क्वांटम और उभरती तकनीकों में सहयोग बढ़ा

--:15:--

Daily Current Affairs

Date : 21 May, 2026

UTKARSH
CLASSES

CIVIL
SERVICES

मुख्य बिन्दु:

1. संयुक्त अरब अमीरात यात्रा: 15 मई, 2026



- यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और पिछले 25 वर्षों में कुल मिलाकर निवेश का सातवाँ सबसे बड़ा स्रोत है। यूएई में 45 लाख से अधिक भारतीय समुदाय रहते हैं।

--:16:--

Daily Current Affairs

Date : 21 May, 2026



- **व्यापार और निवेश संबंध:** दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच द्विपक्षीय व्यापार, व्यापक अर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) के कारण वस्तु व्यापार पहली बार 100 बिलियन डॉलर का आँकड़ा पार करते हुए वित्त वर्ष 2025-26 में 101.25 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया। दोनों पक्षों ने वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 200 बिलियन डॉलर तक ले जाने की प्रतिबद्धता जताई है।

परिणाम सूची:

क्र.सं	क्षेत्र	समझौता ज्ञापन/समझौता	उद्देश्य
1.	ऊर्जा सुरक्षा और सामरिक पेट्रोलियम भंडार (SPR)	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (ISPRL) और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) के बीच रणनीतिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन।	(क) भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में ADNOC द्वारा 30 मिलियन बैरल तक कच्चे तेल का संभावित भंडारण, जिसमें आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में सुविधाओं में इसकी भागीदारी और ओडिशा के चाँदीकोल में आरक्षित सुविधाओं का विकास शामिल हैं। (ख) भारत में तरल प्राकृतिक गैस और तरल पेट्रोलियम गैस भंडारण सुविधाओं में संभावित सहयोग।
2.	सामरिक रक्षा औद्योगिक ढाँचा	सामरिक रक्षा साझेदारी के लिए रूपरेखा।	रक्षा औद्योगिक सहयोग, नवाचार और उन्नत प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण, अभ्यास, शिक्षा और सिद्धांत, विशेष अभियान और अंतरसंचालनीयता, समुद्री सुरक्षा, साइबर रक्षा, सुरक्षित संचार और सूचना विनिमय के लिए एक रणनीतिक रूपरेखा।

--:17:--

Daily Current Affairs

Date : 21 May, 2026



3.	समुद्री अवसंरचना और कौशल विकास	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) और ड्राईडॉक्स वर्ल्ड (DDW)	समुद्री विकास निधि योजना के तहत वडीनार (गुजरात) में जहाज मरम्मत क्लस्टर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
		कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL), ड्राईडॉक्स वर्ल्ड (DDW) और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मैरीटाइम एंड शिपबिल्डिंग (CEMS)	त्रिपक्षीय समझौते के अंतर्गत कुशल समुद्री कार्यबल को जुटाने, प्रशिक्षित करने और रोजगार प्रदान करने के लिए एक रूपरेखा तैयार किया गया है।
4.	उभरती प्रौद्योगिकियाँ और AI	भारत के उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (C-DAC) और UAE के G42 के बीच	AI मिशन इंडिया के अंतर्गत सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर के लिए 8 एक्साफ्लॉप सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करने के लिये एक टर्म शीट पर हस्ताक्षर किये गए।

घोषणा

7.	<p>संयुक्त अरब अमीरात द्वारा भारत में निवेश:</p> <p>(i) भारत के अवसंरचना क्षेत्र में 1 अरब अमेरिकी डॉलर तक के निवेश की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अबू धाबी निवेश प्राधिकरण (ADIA) और भारत के राष्ट्रीय अवसंरचना एवं निवेश कोष (NIIF) को नियुक्त किया जाएगा।</p> <p>(ii) एमिरेट्स न्यू डेवलपमेंट बैंक (ENBD) भारत के RBL बैंक में 3 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा।</p> <p>(iii) अंतर्राष्ट्रीय होल्डिंग कंपनी भारत के सम्मान कैपिटल में 1 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी।</p>
----	--

--:18:--

2. नीदरलैंड यात्रा: 16 से 17 मई, 2026



- नीदरलैंड के प्रधानमंत्री श्री रॉब जेटेन के निमंत्रण पर, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16-17 मई, 2026 को नीदरलैंड की आधिकारिक यात्रा की। यह प्रधानमंत्री मोदी की नीदरलैंड की दूसरी यात्रा थी (पहली; वर्ष 2017)।
- **प्रमुख उपलब्धियों का विवरण:** इस यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक "रणनीतिक साझेदारी" में उन्नत करने और व्यापक "भारत-नीदरलैंड रणनीतिक साझेदारी का रोडमैप (2026-2030)" को अपनाने पर सहमति व्यक्त की।

क्र.सं.	दस्तावेज / समझौते (14 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर)	क्षेत्र
1	भारत-नीदरलैंड रणनीतिक साझेदारी रोडमैप [2026-2030]	व्यापक दस्तावेज
2	चोल राजवंश के ताम्रपत्रों की वापसी	संस्कृति
3	धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब को सहयोग प्रदान करने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ASML के बीच समझौता ज्ञापन	सेमीकंडक्टर

Daily Current Affairs

Date : 21 May, 2026



4	भारत के खान मंत्रालय और नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय के बीच क्रिटिकल मिनरल्स पर समझौता ज्ञापन	क्रिटिकल मिनरल्स
5	गुजरात की कल्पसर परियोजना के संबंध में तकनीकी सहयोग के लिए भारत के जल शक्ति मंत्रालय और नीदरलैंड के मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वॉटर मैनेजमेंट के बीच आशय पत्र	जल
6	“जल रणनीतिक साझेदारी” (मूल रूप से वर्ष 2022 में हस्ताक्षरित) को मार्च, 2027 तक नवीनीकृत करने की प्रतिबद्धता, जिसकी समीक्षा एक मंत्रिस्तरीय संयुक्त कार्य समूह द्वारा की जाएगी।	
7	हरित हाइड्रोजन सहयोग के विकास पर भारत-नीदरलैंड रोडमैप	नवीकरणीय ऊर्जा
8	पश्चिम त्रिपुरा में फूलों (फ्लोरीकल्चर) के लिए इंडो-डच उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना	कृषि / पशुपालन
9	पशुपालन उत्कृष्टता केंद्र (CEAH), बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण पर इंडो-डच उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना	
10	'स्वच्छ पादप केंद्र' की स्थापना	
11	'आपसी कानूनी सहायता संधि' और नई 'प्रत्यर्पण संधि' को अंतिम रूप देने के लिए मिलकर काम करना जारी रखना।	सुरक्षा सहयोग
12	'हिंद-प्रशांत महासागर पहल' (IPOI) में नीदरलैंड्स की सदस्यता के संदर्भ में सहयोग बढ़ाना।	
13	भारत और नीदरलैंड्स के बीच 'ग्रीन एंड डिजिटल सी कॉरिडोर' पर सहमति के आशय पत्र के संदर्भ में सहयोग को और बढ़ाना।	
14.	भारतीय रक्षा निर्माता संघ (SIDM) और रक्षा एवं सुरक्षा के लिये नीदरलैंड के उद्योग (NIDV) के बीच “रक्षा औद्योगिक रोडमैप” जारी।	

--:20:--



अफस्लुइटडिज्क बांध:



- भारतीय प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की प्रतिष्ठित जल प्रबंधन संरचना, अफस्लुइटडिज्क का भ्रमण किया।
- यह 32 किलोमीटर लंबा है जो नीदरलैंड के बड़े हिस्से को उत्तरी सागर से बचाता है और साथ ही मीठे पानी के भंडारण को भी संभव बनाता है।

कल्पसर परियोजना:

- बाँध के भ्रमण ने गुजरात राज्य में अफस्लुइटडिज्क और भारत की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के बीच समानताओं पर प्रकाश डाला।
- कल्पसर परियोजना का उद्देश्य खंभात की खाड़ी में एक मीठे पानी का जलाशय बनाना है, जो ज्वारीय बिजली उत्पादन, सिंचाई और परिवहन बुनियादी ढाँचे को एकीकृत करता है।

चोल ताम्रपत्रों की वापसी:



- दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में लाइडेन विश्वविद्यालय पुस्तकालय ने 11वीं शताब्दी के चोल ताम्रपत्र भारत सरकार को लौटा दिए।
- चोल ताम्रपत्र, जिनमें 21 बड़े ताम्रपत्र और 3 छोटे ताम्रपत्र सम्मिलित हैं, 11वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान चोल राजाओं द्वारा जारी किए गए शाही अभिलेख हैं।
- यह अभिलेख अनैमंगलम ग्राम को तमिलनाडु के नागपट्टिनम स्थित 'चूलामणिवर्म-विहार' नामक बौद्ध विहार को भेंट किए जाने को औपचारिक रूप प्रदान करते हैं। इन ताम्रपत्रों में तमिल तथा संस्कृत भाषाओं में लिखित पाठ अंकित हैं।

- **व्यापार:** नीदरलैंड यूरोप में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक गंतव्यों में से एक है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 27.8 अरब अमेरिकी डॉलर (2024-25) का है; और भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक है, जिसका कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 55.6 अरब अमेरिकी डॉलर है।
- नीदरलैंड्स में यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय निवास करता है। साथ ही, सांस्कृतिक को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2011 से हेग में "द गांधी सेंटर" (ICCR सांस्कृतिक केंद्र) स्थापित किया गया है।

3. स्वीडन यात्रा: 17 से 18 मई, 2026



- 'रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस' सम्मान: स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 'रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस' से सम्मानित किया। यह स्वीडन के सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है, जिसकी स्थापना 18वीं शताब्दी में की गई थी।
- यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को किसी विदेशी देश से प्राप्त होने वाला 31वाँ अंतर्राष्ट्रीय सम्मान बन गया है।

- **परिणाम:** भारत-स्वीडन संबंधों की रणनीतिक साझेदारी; यह रणनीतिक साझेदारी चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित होगी:
 1. स्थिरता और सुरक्षा के लिए रणनीतिक संवाद
 2. अगली पीढ़ी की आर्थिक साझेदारी
 3. उभरती प्रौद्योगिकियां और विश्वसनीय संपर्क
 4. साथ मिलकर भविष्य का निर्माण- लोग, ग्रह, स्वास्थ्य और लचीलापन।
 - **भारत-स्वीडन संयुक्त कार्य योजना:** इस रणनीतिक साझेदारी को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए, दोनों नेताओं ने भारत-स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाया, जो राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी, सुरक्षा, जलवायु और लोगों के आपसी जुड़ाव के क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है।
4. **नॉर्वे यात्रा: 18 से 19 मई, 2026**



- यह प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी और 43 वर्षों में नॉर्वे की पहली प्रधानमंत्री यात्रा है।

तीसरा नॉर्डिक-भारत शिखर सम्मेलन, 2026:



- प्रधानमंत्री ने 19 मई, 2026 को ओस्लो में आयोजित तीसरे नॉर्डिक-भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे; डेनमार्क की प्रधानमंत्री, सुश्री मेटे फ्रेडरिकसेन; फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो; आइसलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टुन फ्रॉस्टडॉटिर; और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन भी शामिल हुए।
- भारत-नॉर्डिक देशों ने पिछले एक दशक में व्यापार में चार गुना वृद्धि हुई है और भारत में नॉर्डिक देशों का निवेश 200 प्रतिशत तक बढ़ा है।
- इस सम्मेलन में विचारणीय प्रमुख विषयों में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण शामिल हैं।

--:25:--

प्रमुख विशेषताएं:

- रणनीतिक साझेदारी का उन्नयन:** शिखर सम्मेलन ने आधिकारिक तौर पर भारत और नॉर्डिक देशों (डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन) के बीच संबंधों को एक विश्वसनीय हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा दिया।
- व्यापार और आर्थिक एकीकरण:** नेताओं ने भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) के कार्यान्वयन और भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते के समापन पर प्रकाश डाला।
- व्यापार और आर्थिक एकीकरण:** नेताओं ने भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) के कार्यान्वयन और भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते के समापन पर प्रकाश डाला।
- जलवायु कार्रवाई और नीली अर्थव्यवस्था:** आइसलैंड का लीडआईटी2.0 के नए सदस्य के रूप में स्वागत किया गया, जो भारी उद्योगों के कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित एक सार्वजनिक-निजी मंच है।
- प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और रक्षा:** इसरो और नॉर्वेजियन अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक नए फ्रेमवर्क समझौते की घोषणा की गई, साथ ही भारत के आगामी शुक्र ऑर्बिटर मिशन (शुक्रयान 1) के लिए एक स्वीडिश पेलोड की पुष्टि की गई।
- भारत ने इस बात पर जोर दिया कि नॉर्डिक रक्षा कंपनियाँ अब भारतीय रक्षा औद्योगिक गलियारों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का लाभ उठा सकती हैं।

पिछले शिखर सम्मेलन:

- पहला भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन: स्टॉकहोम, स्वीडन (वर्ष 2018)
- दूसरा भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन: कोपेनहेगन, डेनमार्क (वर्ष 2022)
- चौथा भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन: फिनलैंड में आयोजित किया जाएगा।

Daily Current Affairs

Date : 21 May, 2026



- **'द रॉयल नॉर्वे ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस'** सम्मान: भारतीय प्रधानमंत्री को नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम ने ओस्लो में आयोजित एक विशेष समारोह में 'द रॉयल नॉर्वे ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस' से सम्मानित किया। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को प्रदान किया जाने वाला यह पुरस्कार नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान है। यह सम्मान नॉर्वे तथा मानवता के हित में उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।

परिणाम:

- **हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI):** नॉर्वे ने भारत की 'हिंद-प्रशांत महासागर पहल' में शामिल होने की घोषणा की, जो यह "क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास" (SAGAR) दृष्टिकोण पर आधारित है।
- **'ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप':** दोनों देश अपने संबंधों को 'ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप' के रूप में उन्नत करने पर सहमत हुए, जो सतत विकास और हरित प्रगति के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
- **त्रिकोणीय सहयोग समझौता:** भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों को भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) (आधार-UPI-कोविन स्टैक) प्रदान करेंगे।
- **व्यापार लक्ष्य:** दोनों नेताओं ने वर्ष 2030 तक भारत और नॉर्वे के बीच वर्तमान व्यापार के मूल्य को दोगुना करने के लक्ष्य को रेखांकित किया।

- ताकि TEPA के तहत 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके और भारत में एक मिलियन रोजगार के अवसरों का सृजन किया जा सके।

--:27:--

5. इटली यात्रा: 19 से 20 मई, 2026



- यात्रा के अंतिम चरण में, इटली गणराज्य की प्रधानमंत्री सुश्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री 19 से 20 मई 2026 को इटली की आधिकारिक यात्रा सम्पन्न की।
- प्रधानमंत्री ने पिछली बार जून, 2024 में G7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली का दौरा किया था।
- इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत-इटली सहयोग को बढ़ावा देना है, जिसमें विशेष रूप से भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) पर ध्यान केंद्रित किया गया।

Daily Current Affairs

Date : 21 May, 2026



- **'एग्रीकोला मेडल'** : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली के रोम में स्थित खाद्य और कृषि संगठन (F.A.O) के मुख्यालय में प्रतिष्ठित 'एग्रीकोला मेडल' से सम्मानित किया गया। (F.A.O के महानिदेशक क्यू डोंग्यू ने प्रदान किया)
परिणाम:
- **राजनीतिक संवाद:** दोनों नेताओं द्वारा अपनाई गई 'संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029' के विभिन्न स्तंभों में हासिल की गई ठोस प्रगति की समीक्षा और सराहना की। दोनों नेताओं ने भारत-इटली संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-29 की समीक्षा और विशेष रणनीतिक साझेदारी को रणनीतिक दिशा देने के लिए विदेश मंत्रियों के नेतृत्व में एक तंत्र (मैकेनिज्म) स्थापित करने पर सहमति जताई।
- **आर्थिक सहयोग और निवेश:** दोनों पक्षों ने वर्ष 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने के साझा लक्ष्य की पुनः पुष्टि की।
- दोनों प्रधानमंत्रियों ने 'क्रिटिकल मिनरल्स' यानि महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- **कनेक्टिविटी:** दोनों प्रधानमंत्रियों ने 'भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे' (IMEC) पर सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
- **विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और कृत्रिम बुद्धिमत्ता:** भारत में स्थित "INNOVIT India" नामक नवाचार केंद्र की स्थापना की घोषणा की जिसका उद्देश्य दोनों देशों के नवाचार तंत्रों के बीच सहयोग को मजबूत करना, स्टार्टअप कार्यक्रमों, बाजार पहुंच, संयुक्त अनुसंधान, विश्वविद्यालय सहयोग और प्रतिभा गतिशीलता को बढ़ावा देना है।
- **प्रवासन और गतिशीलता:** "ICI- इटली कॉल्स इंडिया: ए यूनिवर्सिटी-एंटरप्राइज टैलेंट ब्रिज" पहल की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य इतालवी विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत भारतीय छात्रों की प्रतिभा को मार्गदर्शन, उपयुक्त अवसरों से जोड़ने और इतालवी उद्यमों में योग्य एकीकरण के ठोस रास्ते उपलब्ध कराकर बढ़ावा देना है।
- **संस्कृति और शैक्षिक आदान-प्रदान:** दोनों नेताओं ने वर्ष 2027 को "भारत और इटली के बीच संस्कृति और पर्यटन वर्ष" के रूप में मनाने की मंशा व्यक्त की।

-:29:-

भूगोल एवं भू-विज्ञान

"अरुणाचल कीवी: अरुणाचल प्रदेश की USP" मिशन

{स्रोत: PIB}

चर्चा में क्यों?

- 20 मई, 2026 को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ने "अरुणाचल कीवी: अरुणाचल प्रदेश की यूएसपी - अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए क्लस्टर-आधारित कीवी खेती और मूल्य श्रृंखला विकास मिशन" की शुरुआत की।



मुख्य बिन्दु:

- मिशन की आवश्यकता:** किसानों को ग्रेड सी की पैदावार के लिए सिर्फ ₹20-40 प्रति किलो और ग्रेड ए के लिए लगभग ₹120 प्रति किलो मिलते हैं; जबकि आयातित कीवी की भारतीय और वैश्विक बाजारों में कीमतें काफी ज्यादा होती हैं।

--:30:--

Daily Current Affairs

Date : 21 May, 2026



- **शुभारंभ:** 20 मई, 2026 को जीरो वैली और दिरांग से।
- **रणनीतिक स्तंभ:** यह मिशन चार रणनीतिक स्तंभों पर आधारित है - तालमेल, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और बाजार एकीकरण।
- **मुख्य लक्ष्य:** कीवी की शेल्फ लाइफ बढ़ाना, मजबूरी में कीवी बेचने की समस्या कम करना, 2,000 एमटी की कोल्ड-चेन क्षमता बनाना, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की सुविधाओं को बेहतर बनाना, कीवी से जुड़े स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और वित्त वर्ष 2028 तक अरुणाचल की जैविक कीवी को अंतर्राष्ट्रीय निर्यात बाजारों में पहचान दिलाना।
- **परिचय:** लगभग ₹167 करोड़ के खर्च के साथ, 'अरुणाचल कीवी पर मिशन: अरुणाचल प्रदेश की यूएसपी' को एक 'समग्र-सरकारी', तालमेल-आधारित दृष्टिकोण के जरिए तैयार किया गया है।
- **नेतृत्व:** पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- **सहयोगी:** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाओं के साथ-साथ नाबार्ड, ICAR-CITH, एपीडा, NERAMAC और समर्पित निजी निवेशक।
- **क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण:** यह मिशन एक क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण अपनाता है, जिसके तहत जीरो वैली (लोअर सुबनसिरी), दिरांग और कलाकतांग (वेस्ट कामेंग), शि योमी, और दिबांग घाटी में छह एकीकृत क्लस्टर-स्तरीय 'फसल-बाद प्रबंधन हब' (पोस्ट-हार्वैस्ट मैनेजमेंट हब्स) की पहचान की गई है।
- **अरुणाचल कीवी की स्थिति:** भारत के कुल कीवी उत्पादन में 50 प्रतिशत से ज्यादा का योगदान देने और हर साल 7,050 एमटी से ज्यादा उत्पादन किया जाता है।

--:31:--

Daily Current Affairs

Date : 21 May, 2026



- अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे बड़ा कीवी उत्पादक राज्य है और देश का पहला ऐसा राज्य है जिसे MOVCD-NER (वर्ष 2020) के तहत जैविक कीवी का प्रमाणन मिला है।
- अरुणाचल प्रदेश की ऊंची जगहों वाली, जैविक खेती के लिए अनुकूल जलवायु परिस्थितियों में, कीवी की बेहतरीन किस्मों - हेवर्ड और एलिसन - को उगाने की बहुत ज्यादा संभावनाएँ हैं।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

"ब्रांड नॉर्थ ईस्ट" विजन: हर राज्य के लिए एक खास पहचान (USP) है:

1. सिक्किम - जैविक राज्य
2. मिजोरम - अदरक
3. नागालैंड - कॉफी
4. मेघालय - लाकाडोंग हल्दी
5. त्रिपुरा - क्वीन पाइनएप्पल
6. अरुणाचल - जैविक कीवी

भारतीय शासन एवं राजव्यवस्था

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968

(News on air)

चर्चा में क्यों?

- न्यायाधीश जाँच समिति ने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

The Judges (Inquiry) Act, 1968



मुख्य बिन्दु:

- यह समिति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए गठित की गई थी।

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968

- यह अधिनियम उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कदाचार या अयोग्यता की जांच और उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया को विनियमित करता है।

--:33:--

प्रक्रिया:

- लोकसभा के मामले में 100 सदस्यों द्वारा तथा राज्यसभा के मामले में 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित 'पद से हटाने का प्रस्ताव' लोकसभा अध्यक्ष /राज्यसभा के सभापति को दिया जाता है।
- यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो पीठासीन अधिकारी आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक समिति गठित करते हैं। इसके सदस्यों में प्रायः उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात न्यायविद शामिल होते हैं।
- कदाचार या अक्षमता सिद्ध होने पर इस प्रस्ताव को दोनों सदनों को एक ही सत्र में विशेष बहुमत (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई) से पारित करना होता है।
- इसके बाद, न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति को एक अभ्यावेदन भेजा जाता है।

योजनाएँ एवं नीतियाँ

व्यापार सक्षमीकरण और बाजार-पहुंच (TEAM - टीम) पहल

(PIB)

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय 'टीम' (TEAM) पहल के माध्यम से भारत के सबसे लघु व्यवसायों के डिजिटल रूपांतरण को गति दे रहा है।

मुख्य बिन्दु:

टीम (TEAM) पहल

- TEAM का पूर्ण रूप है: ट्रेड इनेबलमेंट एंड एक्सेस टू मार्केट।
- योजना का प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक योजना। इसे 2024 में शुरू किया गया।
- उद्देश्य: सूक्ष्म और लघु उद्यमों को एंड-टू-एंड ई-कॉमर्स सहायता प्रदान करना, ताकि वे 'ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स' के माध्यम से डिजिटल कॉमर्स में प्रभावी ढंग से भाग ले सकें।
- यह विश्व बैंक द्वारा समर्थित 'रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉरमेंस' (RAMP) कार्यक्रम के तहत एक परिवर्तनकारी उप-योजना है।
- MSMEs की कार्यान्वयन क्षमता और पहुंच बढ़ाने के लिए 2022 में RAMP कार्यक्रम शुरू किया गया था।
- कार्यान्वयन अवधि: 2024 से 2027 तक 3 वर्ष।
- कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC)।

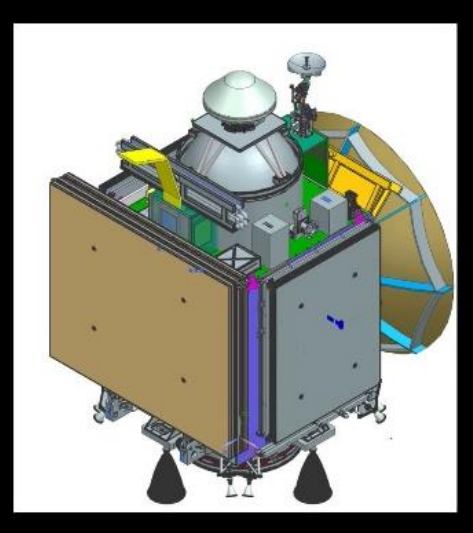
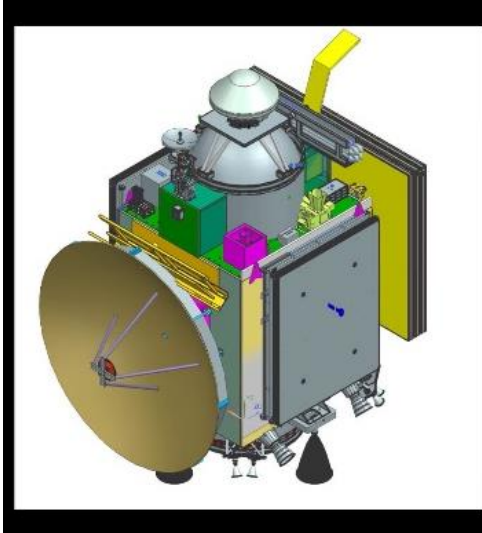
⌚ विज्ञान प्रौद्योगिकी ⚡

वीनस ऑर्बिटर मिशन (VOM)

(times of India)

📢 चर्चा में क्यों?

- स्वीडन भारत के 'शुक्रयान' (वीनस ऑर्बिटर) मिशन में शामिल हुआ।



📌 मुख्य बिन्दु:

- शुक्र, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। माना जाता है कि इसका निर्माण पृथ्वी की समान परिस्थितियों में हुआ था।

वीनस ऑर्बिटर मिशन (VOM)

- यह शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया भारत का पहला वैज्ञानिक मिशन है। इसे 2024 में मंजूरी दी गई थी।
- **उद्देश्य:** शुक्र ग्रह की सतह और उपसतह, वायुमंडलीय प्रक्रियाओं और शुक्र के वायु मंडल पर सूर्य के प्रभाव की बेहतर समझ विकसित करना।
- इसे मार्च, 2028 में प्रक्षेपित करने की योजना है।
- अंतरिक्ष यान के विकास और प्रक्षेपण की जिम्मेदारी इसरो की होगी।

हॉप प्रयोग

(Indian express)

चर्चा में क्यों?

- वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के शिव शक्ति लैंडिंग स्थल पर चंद्रमा की ऊपरी सतह से जुड़ी महत्वपूर्ण नई जानकारियां प्रस्तुत की हैं। ये "हॉप" प्रयोग के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर प्राप्त हुई हैं।

मुख्य बिन्दु:

हॉप प्रयोग

- विक्रम लैंडर की निर्धारित सक्रिय मिशन अवधि के अंत में किए गए इस संचालन ने ISRO की 'लैंडर के इंजनों को दोबारा प्रज्वलित करने की क्षमता' को प्रदर्शित किया।
- इस थ्रस्ट ने यान को सफलतापूर्वक चंद्र सतह से ऊपर उठाया, जिससे भविष्य के सैंपल-वापसी मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षमता सिद्ध हुई।

प्रयोग के प्रमुख निष्कर्ष

- **परतदार संरचना:** चंद्रमा की सतह पर स्पष्ट रूप से "केक जैसी" कई परतें पाई गई हैं, जो लंबे समय तक सूक्ष्म उल्कापिंडों के टकराव से बनी हैं।
- **मृदा में विविधता:** चंद्रमा की मृदा, सतह के कुछ सेंटीमीटर नीचे अधिक घनी और सघन हो जाती है।
- **संध्या कालीन तापीय परिवर्तन:** 'चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट (ChaSTE)' ने चंद्रमा के वायुरहित वातावरण के कारण संध्या समय तापमान में तेज गिरावट दर्ज की।

बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति (PRAGATI), 2026

(स्रोत: PIB और DD-NEWS)

चर्चा में क्यों?

- 20 मई, 2026 को मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति-2026 का शुभारंभ हुआ।



मुख्य बिन्दु:

- प्रगति (PRAGATI) का अर्थ:** "हिंद महासागर क्षेत्र में विकास और परिवर्तन के लिए क्षेत्रीय सेनाओं की साझेदारी" (PRAGATI - Partnership of Regional Armies for Growth and Transformation in the Indian Ocean Region)
- भागीदार:** इस सैन्य अभ्यास में भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम सहित 12 मित्र देशों ने भागीदारी कर रहे हैं।
- दो सप्ताह तक संचालित होने वाले इस अभ्यास में अर्ध-पहाड़ी और जंगली इलाकों में आतंकवाद-विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
- उद्देश्य:** भाग लेने वाले सैनिकों की अनुकूलन क्षमता, सहनशक्ति और सामरिक दक्षता में सुधार करना।

अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल (ULPGM-V3)

(स्रोत: PIB)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल स्थित राष्ट्रीय मुक्त क्षेत्र रेंज (NOAR) में मानवरहित हवाई वाहन द्वारा प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल (ULPGM-V3) का सफल उड़ान परीक्षण किया।



मुख्य बिन्दु:

- परीक्षण:** इस मिसाइल को बेंगलुरु स्थित भारतीय स्टार्टअप न्यूस्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजीज द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित यूएवी (UAV) से छोड़ा गया।
- परिचय:** ULPGM-V3 एक ड्रोन द्वारा लॉन्च की जाने वाली सटीक मिसाइल है जो जमीनी लक्ष्यों और दुश्मन के हवाई लक्ष्यों दोनों को सटीक रूप से निशाना बना सकती है।

--:39:--

Daily Current Affairs

Date : 21 May, 2026



- **उन्नत संस्करण:** यह मिसाइल DRDO द्वारा पहले विकसित और वितरित की गई ULPGM-V2 मिसाइल का उन्नत संस्करण है।
- **विकास:** इस मिसाइल को डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं, जैसे कि रिसर्च सेंटर इमारत, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, हाई-एनर्जी मैटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- **मिसाइल तीन मॉड्यूलर वारहेड विकल्पों से लैस है:** आधुनिक युग के बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए एंटी-आर्मर वारहेड, जो रोल्ड होमोजेनियस आर्मर (RHA) और एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर (ERA) से लैस हैं; एंटी-बंकर उपयोग के लिए पेनिट्रेशन-कम-ब्लास्ट वारहेड; और उच्च घातकता क्षेत्र वाला प्री-फ्रैगमेंटेशन वारहेड।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--:40:--